

**श्री संवर्धन गौतम :** सर, हरियाणा में होता है गयाराम और आयाराम, हरियाणा में... (व्यवधान)...

**श्री गया सिंह :** सभापति महोदय, अभी जो उन्होंने बताया, माइनिंग इंडस्ट्रीज हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह मुख्य रूप से पिछड़े हुये ट्राइबल्स एरिया में है, लेकिन जैसा कि मंत्री जी ने बताया माइनिंग इंडस्ट्रीज में आजादी के बाद कई एरिया में हमारा विकास हुआ, उसका प्रोस्पेक्टिंग हुआ। अभी काफी डिप हो गया और बगल में में उसके विकास के लिये जो कई आइटम्स हैं, वह नहीं कर रहे हैं और जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा हम ज्यादा अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं काफी सस्ते में और दूसरी ओर ह. इंपोर्ट कर रहे हैं सेम मेटेरियल, सेम ग्रेड का मेटेरियल, कई इंडस्ट्रीज में जहां रा-मेटेरियल है वह काफी महंगे में ह. इंपोर्ट कर रहे हैं और देश के अन्दर प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिये मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, खासतौर से स्टील इंडस्ट्रीज में हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारे यहां कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जिनका विकास नहीं कर रहे हैं, तो आप उस ओर क्या ध्यान दे रहे हैं? दूसरी ओर बिहार की कई ऐसी इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्रीज तो काफी डिप हो गई सिंहभूमि में, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया था आपसे और आज बगल में वह जो इंडस्ट्री है, माइनिंग इंडस्ट्री मिली है वहां, चार साल से आप सोच रहे हैं, उस को चालू नहीं किया।

**श्री बलराम सिंह यादव :** मान्यवर, स्टील के बारे में तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिये कि हमारा विषय नहीं है। मगर, इतना जरूर मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इधर जो हम नई पालिसी ला रहे हैं या एम०एम०आर०डी० एक्ट में हम जो संशोधन लाने पर विचार कर रहे हैं, उनकी भावनाओं, का जब हम निर्णय लेंगे तो जरूर उनकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे।

\*166. [The Questioner (Shrimati Basanti Sarma, was absent. For answer vide col.....infra.]

**Text Books for IX Standard in West Bengal**

\*167. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the "Telegraph" (Cal.) of February 8, 1993 under the caption "Commercial bias in West Bengal textbook" referring to "Hindustan Ki Tareekh" prescribed for class DC by West Bengal Board of Secondary Education for Urdu medium schools in the State which contains derogatory remarks against Guru Tegh Bahadur; and

(b) If so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) and (b) A statement is laid on the table of the Sabha.

#### Statement

Text Books for IX Standard in West Bengal

As per information received from the Government Of West Bengal, the book entitled 'Hindustan Ki Tarikh' referred to in the news) item appearing in the newspaper "The Telegraph" dated 8.2.93, has not been approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a textbook. Both the NCERT and the National Steering Committee set up by the Ministry of Human Resource Development to review the school textbooks from the standpoint of national integration have opined that the book presents an inaccurate and distorted version of many aspects of medieval history.

The National Steering Committee has, in its meeting held on 30-31-1.93 recommended, *inter alia* that textbooks which are not authorised should not be allowed to be used in

the schools,, including, those run by private bodies or religious or cultural organisations. The Committee's report containing its recommendations was placed before the Conference of State Education Ministers and Educationists, held in New Delhi on 1.2.1993. As per the decision taken at the Conference, views of the State/UT Governments on the report have been invited for evolving a plan of action both for the Central Government and the State/UT Governments to protect "the secular and national character of school textbooks and other educational material."

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर :** श्रीमान यह बड़ा गंभीर सवाल है, यह सदन में पहले भी उठ चुका है, इस पुस्तक में गुरु तेग बहादुर, शिवाजी और राणा प्रताप के लिए अपमानजनक शब्द कहे गए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, कि आपने यह मोलमाल जवाब दिया है, आखिर में कहा है आपने—

"As per the decision taken in the Conference, views of the State/UT Governments on the report have been invited for evolving a plan of action both for the Central Government and the State/UT Governments..."

आपने यह नहीं बताया कि क्या प्रदेश सरकार से आपने इस पुस्तक के लिखने वाले के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की या नहीं की है? (व्यवधान)

**श्री मोहम्मद सलीम :** यह यू०पी० थोड़े ही है। (व्यवधान)

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर :** क्या आपने पं० बंगाल सरकार से कहा है कि जिसने कितनी लिखी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए? और, जो किनावे पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें गुरु तेग बहादुर, शिवाजी और राणा प्रताप का है, आपने लिखा है कि नैरोगेट, यह खराब है, तो आपने कार्यवाही करने की मांग की है या नहीं की? नहीं की तो क्यों नहीं की?

**श्री अर्जुन सिंह :** आदरणीय सभापति जी, इसमें बहुत साफ रूप से उत्तर दिया गया है कि यह पुस्तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एप्रूव्ड पुस्तक नहीं है और इसलिए जो पुस्तक एप्रूव्ड नहीं है उसका इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। इस और पश्चिम बंगाल सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और वह इस पर नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर :** उस लेखक के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।...

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### Al location of Iron and Steel to Gujarat

\* 163. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of STEEL be pleased to state the steps taken or proposed to be taken to streamline the system of allocation of iron and steel to Gujarat?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): After deregulation of pricing and distribution of iron and steel w.e.f. 16th January, 1992, the requirements of only five sectors; namely; Defence; Railways, Exporters of Engineering Goods, Small Scale Sector and North Eastern \* Region are being met on priority.

The Development Commissioner for Iron and Steel (DCI&S) makes allocation of pig Iron to the five, designated priority sectors. He also allocates steel to exporters of engineering goods, small scale sector and the North-Eastern region. The requirements of the States including Gujarat are duly taken into account by the DCI&S in making allocations of pig iron and steel. Requirements of other consumers are met by Main Producers in accordance with their distribution guidelines.